Inclusive Development

प्रस्तावना -

समावेशी विकास विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करते हैं।

fair

समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता (Inclusiveness) लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन (Sustainability) भी सुनिश्चित करता है। (UPSC Mains)

यदि विकास समावेशी नहीं है तो वह टिकाऊ नहीं रह पाएगा। इसका कारण यह है कि अमीरों की उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति

न केवल कम होती है बल्कि असमानता के बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। इससे समग्र मांग कम होने लगती है और विकास का पतन होने लगता है।

IMF के World Economic Outlook (April 2016) में निम्न महत्वपूर्ण रिसर्च देखने को मिलता है -

'यदि किसी देश की Top 20 % जनसंख्या को 1 % अतिरिक्त आय transfer की जाती है तो उसकी GDP की ग्रोथ रेट 0.08 बिन्दुओं से कम हो जाती है।

इसी प्रकार, यदि Bottom 20 % जनसंख्या को 1 % अतिरिक्त आय transfer की जाती है तो उसकी GDP ग्रोथ रेट 0.38 बिन्दुओं से बढ़ जाती है।'

भारत में समावेशी विकास का लक्ष्य
11 वीं पँचवर्षीय योजना में पहली बार
लागू किया गया।

वर्तमान में यह SDG-8
के अन्तर्गत सम्मिलित है।

Note - समावेशी विकास Intra-generational equity (अन्त: पीढ़ी समता) से जुड़ा मुद्दा है। (UPSC Mains)

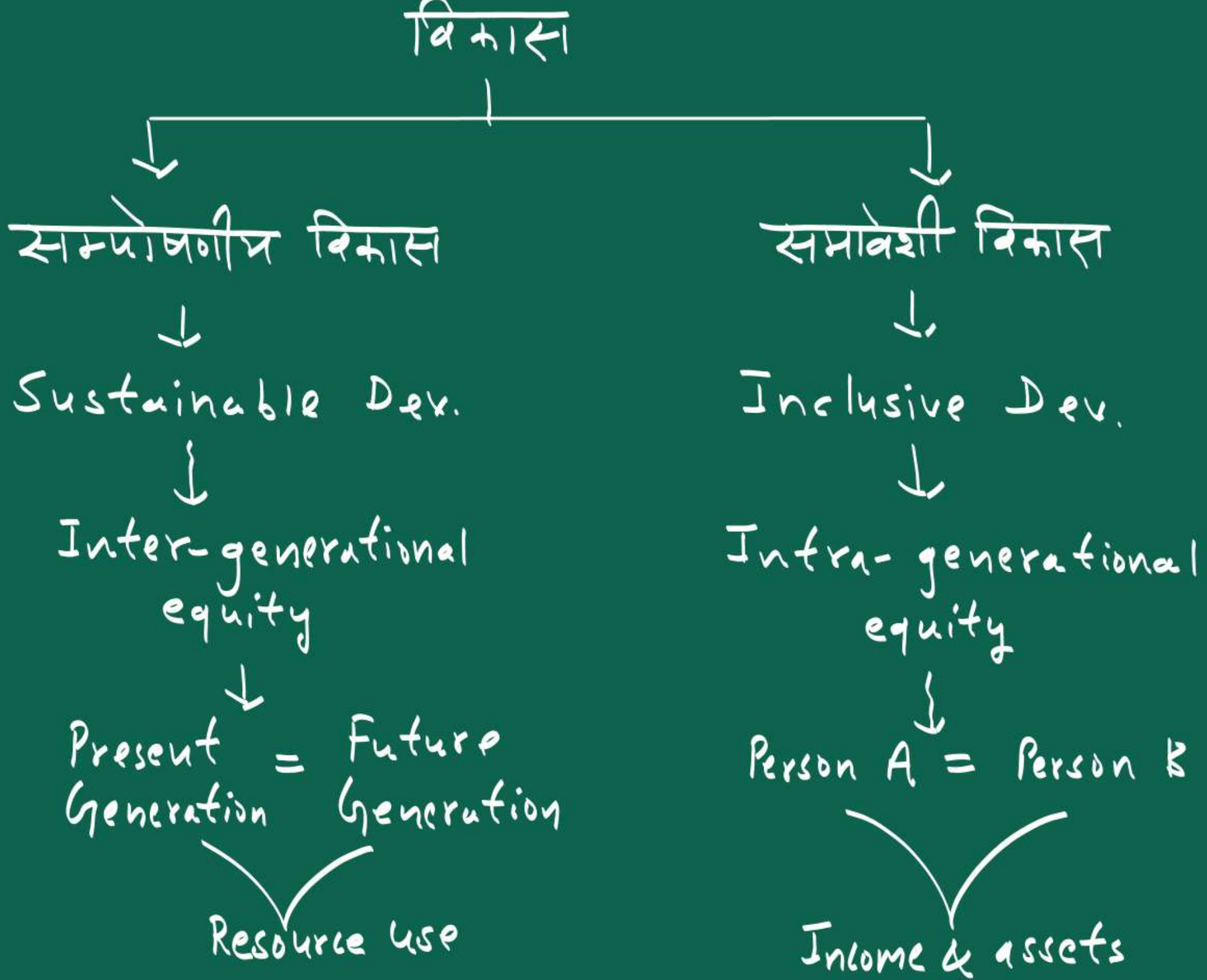

विकास

- सम्पोषणीय विकास
  - Sustainable Dev.
    - Inter-generational equity
      - Present Generation = Future Generation
        - Resource use
- समावेशी विकास
  - Inclusive Dev.
    - Intra-generational equity
      - Person A = Person B
        - Income & assets

क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है?

↓

Yes

(समावेशी नहीं है, अपवर्जी है।)

↓

Exclusionary

Facts to justify

उचित तथ्य -

1. World Inequality Report, 2022

↓

(i) Top 1% लोगों के पास भारत की राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा चला जाता है।

(ii) Top 10% के पास भारत की राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा चला जाता है।

(iii) Top 10% की औसत वार्षिक आय → ₹ 11,66,520
Bottom 50% की औसत वार्षिक आय → ₹ 53,600

2. Survival of the Richest : The India Story
(2023, Oxfam)

↓

(i) भारत की Top 10 % जनसंख्या ।

↓

72 % (कुल सम्पत्ति का)

(ii) Bottom 60 % जनसंख्या ।

↓

3 % (कुल सम्पत्ति का)

3. Inclusive Development Index, 2018
(World Economic Forum)

↓

भारत की Rank

↓

(62)

Conclusion - इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में विकास समावेशी नहीं है।

भारत में किस प्रकार समावेशी विकास लाया जा सकता है ?

↓

(i) सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाना।

(ii) सभी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पहुँच का विस्तार करना।

(iii) सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) सुनिश्चित करना। (Mains 2015)

(iv) प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करना।

(v) Social expenditure (सामाजिक खर्च) के स्तर को बढ़ाना।

(vi) अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कम करना और प्रत्यक्ष करों का अधिक प्रयोग करना।

उपर्युक्त के अलावा, निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जा सकता है -

(i) गरीबी निवारण की व्यापक रणनीति
↓
लागू ।

(ii) ग्रामीण इन्फ्रा को मजबूत करना ।
↓
PURA - Providing Urban Amenities in Rural Areas

(iii) पिछड़े राज्यों में निवेश । → प्रोत्साहन

(iv) कुशलता - विकास पर ज़ोर।

(v) त्वरित कृषि विकास पर ज़ोर।

(vi) ग़ैर-कृषि गतिविधियों (Non-farm activities) को बढ़ावा।

↓

पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग आदि।

Rural Industrialisation
ग्रामीण औद्योगिकीकरण

(vii) लिंग - सन्तुलन की नीतियों को लागू करना।

(viii) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के

विकास और सशक्तिकरण पर जोर देना।

(ix) लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) उपलब्ध करवाना।

(x) रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुनिश्चित करना। आदि।

Conclusion :

इस प्रकार, उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करके समावेशी विकास के लिये एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।

Production

Income	Consumption	उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति
₹100	₹90	0.9
₹1000	₹900	0.9
₹1,00,000	₹80,000	0.8
₹10,000,00	₹7,00,000	0.7
₹1 crore	₹50 लाख	0.5
₹100 crore	₹10 करोड़	0.10